**Regarding payment of pending wages and other related issues under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Rajasthan-Laid**

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(**बाड़मेर**) :** मैं सरकार का ध्यान राजस्थान के रेगिस्तानी एवं अति-दूरस्थ पंचायतों में मनरेगा मजदूरी भुगतान में हो रही गंभीर देरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । वर्ष 202324 में 14.3 करोड़ सक्रिय श्रमिकों की संख्या 202425 में घटकर 13.2 करोड़ रह गई है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार नहीं मिल पा रहा है । पश्चिमी राजस्थान के मरु-क्षेत्रों में इस स्थिति ने श्रमिकों की आय, पोषण सुरक्षा और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है । 202425 चक्र की लंबित मजदूरी के कारण अनेक श्रमिक महीनों से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं कई पंचायतों में जॉब-कार्ड अनुमोदन में अनावश्यक वि लं ब से नए-पुराने श्रमिक कार्य से वंचित हैं । पूर्ण कार्य निष्पादन के बाद भी भुगतान लंबित होना ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ा रहा है । अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि लंबित मजदूरी का समयबद्ध भुगतान, जॉ ब-कार्ड प्रक्रिया का सरलीकरण, सामाजिक ऑडिट की विशेष समीक्षा तथा राज्यवार लंबित राशि के आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए जाएँ । इसके अतिरिक्त, मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि लंबे समय से मनरेगा कार्यों में लगे हुए श्रमिकों का बकाया भुगतान तत्क्षण जारी किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके ।